

प्रेशक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आजमगढ़, बुलन्दशहर, मिर्जापुर, सहारनपुर, भदोही, वाराणसी, आगरा, बरेली,  
गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, मेरठ, गाजियाबाद, मऊ, मथुरा, इटावा, रामपुर,  
लखनऊ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर,  
बहराइच, श्रावस्ती, बदायूँ, उन्नाव, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, बस्ती, बांदा,  
हरदोई, गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, एटा, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद,  
अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, कौशांबी, बिजनौर।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 23 मार्च, 2010  
विशय: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित विशेष बाल  
श्रमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू किए जाने के संबंध  
में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित  
विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों को सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के समकक्ष मानते  
हुए मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित करने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध  
में निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा श्रम आयुक्त, उ०प्र० के पत्र संख्या-117  
दिनांक-04.01.10 के माध्यम से प्राप्त उपरोक्त 46 जनपदों की सूची उपलब्ध करायी  
गयी है, जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रमिक विद्यालय  
संचालित हैं।

2. भारत सरकार के उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि  
प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत संचालित विशेष बाल श्रमिक  
विद्यालयों को मध्याह्न भोजन योजना के परिप्रेक्ष्य में सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों  
के समान मानते हुए मध्याह्न भोजन योजना के प्राथमिक स्तर हेतु अनुमन्य मासिक के  
अनुसार अपने जनपद के सभी विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों  
को दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से मध्याह्न भोजन दिया जाना सुनिश्चित करें।

3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत संचालित उक्त संदर्भित विद्यालयों में  
मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु कार्यवाही संस्था का निर्धारण जिला स्तर पर  
जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित विकल्पों में से किया जायेगा-

• शासनादेश संख्या-1429/79-6-04-1(6)/2000 टी.सी.-3 दिनांक 25

जून, 2004 एवं 981/79-6-04-1(6)/2000 टी.सी.-8 दिनांक-8 सितम्बर,

2004 के अंतर्गत गठित ग्राम स्तरीय/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा।

• जनपद में पहले से योजना का संचालन कर रहे एन०जी०ओ० द्वारा।

• स्वयं सहायता समूह द्वारा।

1/2/10

- जनपद में उपलब्ध महिला समाख्या समिति के संघो द्वारा।
- एन०सी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत संचालित विशेष श्रमिक स्कूलों को संचालित करने वाले एन०जी०ओ० द्वारा।
- जिले स्तर पर श्रम विभाग के अन्तर्गत गठित एन०सी०एल०पी सोसायटी द्वारा।

4. इन विशेष श्रमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालन में उपभोग होने वाले खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत और रसोइये के मानदेय पर हुये व्यय का विवरण पृथक से रखते हुये प्रत्येक त्रैमास में उपभोग प्रमाण-पत्र संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से मध्याह्न भोजन प्राधिकरण एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय संख्या-826 /दस-2010 दिनांक- 23-3-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

*A. Chander*  
(अनूप चन्द्र पाण्डेय)  
प्रमुख सचिव।

**पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
5. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त नियंत्रक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), उत्तर प्रदेश।
9. संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. सम्बन्धित सहायक श्रमायुक्त/परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, उ०प्र०।
13. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (ई-11)/बजट अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

*20*  
(सी०पी० सिंह)  
अनु सचिव।